

मॉरीशस में भारतीय परियोजना का वरिध

चर्चा में क्यों?

मॉरीशस में अगलेगा द्वीपों पर सुवधाओं को अपगरेड करने के लिये हृदि महासागर में भारत की प्रमुख परियोजनाओं में से एक पर काम चल रहा है लेकिन मॉरीशस की संसद और स्थानीय लोगों द्वारा इस परियोजना का वरिध कथिा रहा है ।

पृष्ठभूमि

वर्ष 2015 में भारत ने अगलेगा द्वीप समूह के वकिकास के लिये मॉरीशस के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर कथिे थे । इस समझौते के तहत नमिनलखिति कार्यों को शामिल कथिा गया था-

- समुद्र और वायु संपर्क में सुधार के लिये बुनयिादी ढाँचे की स्थापना और उन्नयन ।
- द्वीप से बाहर में अपने हतिों की रक्षा के लिये मॉरीशस सुरक्षा बलों की क्षमताओं को बढ़ाना ।
- हालौक, भारतीय नौसेना और तटरक्षक बल अपने हतिों की रक्षा के लिये ट्रांसपोंडर ससि्टम और नगिरानी बुनयिादी ढाँचे को स्थापति करने में रूचि दखिा रही है, जनिका स्थानीय स्तर पर वरिध कथिा जा रहा है ।

अगलेगा परियोजना

- इस परियोजना में एक जलबंधक या सेतु (Jetty) का नरिमाण, रनवे का पुनर्रनरिमाण और वसितार तथा मॉरीशस के मुख्य भू-भाग के उत्तर में स्थति अगलेगा द्वीप पर एक एयरपोर्ट टर्मिनल का नरिमाण कथिा जाना शामिल है ।
- 87 मिलियन डॉलर की लागत वाली इस परियोजना को भारत सरकार द्वारा वतितीय सहायता उपलब्ध कराई जा रही है ।

भारत के लिये परियोजना का महत्त्व

- मात्रा के आधार पर भारत के व्यापार का कुल 95% तथा मूल्य के आधार पर 68% व्यापार हृदि महासागर के माध्यम से होता है । भारत द्वारा आयात कथिे जाने वाले कुल कचचे तेल का 80% भाग हृदि महासागर के मार्ग से आयातति होता है, इसलिये हृदि महासागर में भारत की उपस्थति महत्त्वपूर्ण है ।
- चीन का 'स्ट्रगि ऑफ परल्स' जो भारत के सामरकि हतिों के लिये एक खतरा हो सकता है, का मुकाबला करने के लिये हृदि महासागर के वृहद क्षेत्र में भारत की उपस्थति अत्यंत आवश्यक है ।
- इस परियोजना को SAGAR (Security And Growth for All in Region) परियोजना के तहत अपने पड़ोसी देशों के वकिकास के प्रयासों के हसिसे के रूप में देखा जा सकता है । इस परियोजना को भारत और इसके पड़ोसी देशों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने के रूप में भी देखा जा सकता है ।
- मालदीव और सेशेल्स में भारतीय परियोजनाओं द्वारा प्रतरिध का सामना कथिे जाने के बाद भारत के लिये यह अधिक आवश्यक है कविह अपनी परियोजनाओं को सफलतापूर्वक लागू करे ।
- यह परियोजना आधारभूत ढाँचे के उन्नयन के माध्यम से मॉरीशस के सुरक्षा बलों की क्षमता में वृद्धिकरेगा ।

परियोजना के वरिध का कारण

1. वपिक्ष द्वारा वरिध

- मॉरीशस की संसद में वपिक्ष इस परियोजना की पारदर्शति पर सवाल खड़े कर रहा है ।
- परियोजना में भारतीय भागीदारी और इसकी लागत को लेकर समस्याएँ हैं और यह समस्या भी है ककिया इसमें भारतीय सैन्य घटक शामिल होगा ।
- मॉरीशस की सरकार ने इस परियोजना को कसिी भी पर्यावरणीय लाइसेंस प्रक्रयिा से छूट प्रदान की है ।

2. स्थानीय लोगों द्वारा वरिध

- 1965 में मॉरीशस की आज़ादी से पहले, ब्रटिन ने मॉरीशस से चागोस द्वीप को अलग कर दथिा था और जबरन वहाँ के नविसयिों को स्थानांतरति कर दथिा तथा अमेरिका को डरिगो गार्सयिा पर सैन्य अड्डा बनाने की इज़ाज़त दी । भारतीय परियोजना को लेकर अगलेगा द्वीप के नविसयिों के मन में यही

भय है कि कहीं उनके साथ पहले जैसा व्यवहार न हो।

- सभी बड़ी सैन्य शक्तियाँ जैसे- फ्रांस, चीन, अमेरिका और ब्रिटेन हृदय महासागर में नौसैनिकी आधार विकसित कर चुकी हैं, जिसके चलते स्थानीय लोगों को भय है कि उनके शांत द्वीप का सैन्यीकरण कर दिया जाएगा।

आगे की राह

- अन्य देशों द्वारा संचालित सैन्य अड्डों के विपरीत, भारतीय अड्डों का आधार नरम है जिसका अर्थ है कि स्थानीय लोग किसी भी भारत निर्मिति परियोजना के माध्यम आवागमन कर सकते हैं। इससे स्थानीय सरकारों को अपनी संप्रभुता को कम कथि बना, अपने क्षेत्र पर अधिक नियंत्रण प्राप्त होता है। भारत को सभी प्रभावित पार्टियों के डर को दूर करके और अधिक प्रेरक तरीके से एक विश्वसनीय तथा दीर्घकालिक साझेदार के रूप में खुद को पेश करने की ज़रूरत है।

स्रोत : द हिंदू

PDF Reference URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/india-project-in-mauritius-faces-protests>

